रेल मजदूरों! 12 फ़रवरी की सर्व हिंद हड़ताल का पुरजोर समर्थन करो!

कामगार एकता कमिटी का बयान, ११ फ़रवरी २०२६

रेल मजदूर भाइयों और बहनों,

12 फ़रवरी के दिन, पूरे देश के करोड़ो मजदूर और किसान हड़ताल संघर्ष कर रहे हैं। मजदूर उनके फैक्ट्री गेटों एवं दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेंगे तथा अनेक जगहों पर किसान बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंश्योरंस, बिजली, टेलीकोम, पोस्ट, खदान, रक्षा सामग्री का उत्पादन करनेवाले उद्यम, पोर्ट और डॉक आदि कई उद्यमों के मजदूर और उनकी युनियनें हड़ताल में शामिल होने का निश्चय अब तक घोषित कर चुके हैं।

देश के करोड़ो मजदूर एवं किसान सरकारों की जिन नीतियों एवं कानूनी प्रावधानों तथा बदलावों का लगातार विरोध कर रहे हैं, उन्ही नीतियों को सरकारें जबरदस्ती से थोप रही हैं। इन सरकारों का यह तानाशाही रवैया इन सब के आक्रोश का मुख्य कारण है।

रेल मजदूर भाइयों और बहनों,

रेल मजदूरों को भी सरकार की इस तरह की तानाशाही का मुकाबला करना पड रहा है। जब बहुसंख्या में रेल मजदूर OPS की माँग कर रहे हैं तब सरकार जबरदस्ती से NPS थोप रही है। लोको पायलट, मोटरमैन, ट्रेक मेंटेनर, सिग्नल एवं टेलीकोम, स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, टिकट चेकर, ट्रेन कंट्रोलर आदि सभी कैटेगरी के रेल कर्मचारी बार बार माँग कर रहे है की 3.5 लाख से ज्यादा रिक्त पदों की तुरंत भर्ती की जाय। इस के अलावा गत 15 वर्षों में रेलवे की सेवाओं में बेहद बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कितने पदों की आवश्यकता है यह फिर एक बार जाँच कर पद संख्या बढ़ाई जाय और उन में भी भर्ती की जाय। मगर सरकार इसके बिलकुल उल्टा कर रही है एवं हजारों पद सरेंडर कर रही है। रेल मजदूर माँग कर रहे है कि ठेकेदारी प्रथा पूर्णतया बंद की जाय, जबकि सरकार उसे बढ़ा रही है।

इस तरह रेल मजदूरों का आक्रोश एवं देश के सभी मजदूर किसानों का आक्रोश एक ही है - सरकार ने वही करना चाहिए जो देश के बहुसंख्यक, यानि मजदूर - किसान चाहते हैं।

रेल मजदूर भाइयों और बहनों,

“सभी सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण पर तुरंत रोक” यह 12 फ़रवरी के हड़ताल की एक प्रमुख मांग है। जाहिर है कि रेल मजदूरों ने इसका पुरजोर समर्थन करना ही चाहिए।

केंद्र सरकारने जबरन जो 4 श्रम संहिता (लेबर कोड़) लागू किए हैं, उनकी वजह देश के संगठित एवं असंगठित, यानि सभी मजदूरों पर बेहद बुरा असर होगा,यह स्पष्ट है । मिसाल के तौर पर:

- ठेकेदारी प्रथा को और आसान बनाई गई है इसलिए रेलवे में और भी ज्यादा बढ़ेगी।

- न्यूनतम मजदूरी का दर निश्चय ही कम होगा। इसका असर हमारे परिजनों पर भी होगा।
- “फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट” यह आम बात होगी, जिससे नौकरी की भारी असुरक्षा होगी। आज जो मजदूर स्थायी नौकरी कर रहे है, जैसे कि रेलवे मजदूर, उनके बेटे बेटियाँ ज्यादातर इसी तरह की नौकरियों में पिसते रहेंगे।
- उद्योगों के मालिकों को, सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक खर्चा टालना बेहद आसान होगा क्योंकि अब वे खुद ही स्वयं को सर्टिफिकेट देंगे और सरकार उसे सच मानेगी। आज रेल मजदूरों को बेहद असुरक्षित हालातों में काम करना पड़ता है, उसके खिलाफ संघर्ष और भी मुश्किल होगा।
- रेल मजदूरों सहित सभी मजदूरों को हड़ताल संघर्ष करना बेहद और भी मुश्किल होगा।

रेल मजदूर भाइयों और बहनों,

सर्व हिंद आक्रोश का दूसरा मुख्य कारण है “बिजली कानून सुधार अधिनियम 2025” को जबरन थोपने की सरकार की कोशिश। इस कानून में ही स्पष्ट किया गया है कि बिजली वितरण में निजीकरण बढ़ाना इसका एक उद्येश्य है। निजीकरण से रेल मजदूरों और बिजली मजदूरों सहित सभी मजदूरों और किसानों को तेजी से बढ़ते बिजली दर का भार उठाना पड़ेगा।

आक्रोश का तीसरा मुख्य कारण है बढती महंगाई, जिसकी जोर की मार तो सभी पर पड रही है।

आक्रोश का अगला मुख्य कारण है “बीज विधेयक 2025” जिसे केंद्र सरकार जबरन थोपना रही है। इस विधेयक के कारण, बड़ी बड़ी बीज उत्पादक कंपनियों के हाथों किसानों की लूट होगी जिससे देश के सभी मेहनतकश, यानि रेलवे मजदूर भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

इन तथ्योंसे यह स्पष्ट है की रेल मजदूरों ने 12 फ़रवरी की हड़ताल का पुरजोर समर्थन करना चाहिए।रेल मजदूर भाइयों और बहनों ,

हम मजदूरों को यह सोचना भी आवश्यक हो गया है, कि क्या हमारे देश में असल में “जनतंत्र” है? बढ़ती संख्या में मजदूरों में यह सूझ बढ़ रही है कि यह “जनतंत्र” नहीं बल्कि “पूंजीपतियों की मनमर्जी” का तंत्र है। हम आप से भी आवाहन करते हैं कि आइए, हम सब यह सोचना शुरू करें कि कैसे हम अपने देश में मजदूर-किसानों का शासन प्रस्थापित करें।

12 फ़रवरी की सर्व हिंद हड़ताल का पुरजोर समर्थन करें !

मजदूर एकता जिंदाबाद!